

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 36/2020

शैतान सिंह पुत्र स्व. श्री जमनाराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम झड़यानगर, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

-अपीलार्थी-

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू ।

-रेस्पोंडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम शैतान सिंह वगैरह अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 45/2019 निर्णय दिनांक 27.01.2020


उपस्थिति:-

1. श्री सुशील कुमार जोशी, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -----रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 30.09.2022

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.01.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम शैतान सिंह मु0न0 45/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि - अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी में प्रकरण दिनांक 27.01.2020 को नियत था जिस पर अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य अभियोजन में जानी चाहिये थी परंतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आदेशिका पारित की कि- दिनांक 27.01.2020 को पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी उप.। नोटिस जवाब पेश किया। शामिल मिशाल है और कोई जवाब पेश नहीं करना चाहा। जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली में निर्णय बेदखली पृथक से लिखा जाकर शामिल है। पत्रावली फैलल शुमार होकर नंबर से कम है। उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार पटवारी हल्का ने खसरा नंबर 4227/2473 वाके ग्राम झराया नगर के रकबा 0.01 हैक्टर किस्म बंजर 1 में अतिक्रमी द्वारा दुकाने निर्माण जाने


 जिला कलक्टर
 जिला कलक्टर
 झुंझुनू

की रिपोर्ट पेश की। अपीलार्थी द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिये गये जवाब में स्पष्ट अंकित किया है कि तथाकथित भूमि पर जो अतिक्रमण पटवारी हल्का द्वारा करना बताया है वह दुकाने प्रार्थी के पिता के समय की करीब 50 वर्ष पहले बनी हुई हैं, पुराना कब्जा है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन 1994 एवं 2002 के अनुसार उपरोक्त भूमि नियमन होने योग्य है। उपरोक्त परिसर में प्रार्थी के भाई के नाम विद्युत कनेक्शन है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मनमाने तरीके से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो कतई विधिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। आलौच्य निर्णय स्पीकिंग निर्णय की श्रेणी में नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.01.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि— अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विवादित भूमि का मौका निरीक्षण नहीं किया गया, केवल हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है। अपीलांट का पूर्वजों के समय से करीब 50 वर्ष से अधिक समय से विवादित भूमि पर कब्जा हैं एवं विद्युत कनेक्शन आदि जुड़े हुये हैं । अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में अपने निर्णय में कोई टिप्पणी नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय स्पीकिंग निर्णय की श्रेणी में नहीं आता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.01.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा

अति. जिला कलेक्टर
2024

को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करेंगे तथा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अपीलांटस द्वारा पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज का विधिक रूप से परीक्षण कर राज्य सरकार के परिपत्रों के मध्यनजर बंजड-II की भूमि पुराने कब्जे के आधार पर नियमन योग्य है अथवा नहीं बाद परीक्षण पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



30.9.2022
(जगदीश प्रसाद मौरा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9
(जगदीश प्रसाद मौरा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू